कि इसके लिए आयु का काल बढ़ाने की दृष्टि से विचार चल रहा है, इसलिए इसके पश्चात् ही यह रिक्त पद भरा जाएगा। अंत में मैं इस विषय पर कह सकती हूं कि 17 नवंबर, 1999 को पुनर्निर्धारित किया गया और दो उम्मीदवारों के पैनल की सिफारिश की गई है और शीघ्र ही उस पद को भरा जाएगा।

श्री शंकर राय चौधरी: माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य का सवाल था कि जो रिक्त पद हैं, उनमें ज्वाइंट सेक्रेटरी को क्यों न नियुक्त किया जाए। मैं माननीया मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि मुझे इसमें आई.ए.एस. लॉबी की अपने पंख फैलाने की कोई साज़िश लगती है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी पोस्ट्स के लिए वे क्वालिफाईड टेक्नोक्रेट्स को लें।

श्रीमती जयवंती मेहता: आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा।

Power Plants by Foreign Power Companies in Gujarat

*622. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the details of foreign power companies permitted to set up power plants in Gujarat;

(b) the name of the companies which have set up such plants;

(c) whether there are some projects which have sought clearance pending with Government;

(d) the reasons for pendency; and

(e) the extent to which the power shortage will be reduced?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI JAYAWANTI MEHTA): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) M/s Siemens, Germany and M/s Power Gen. U.K. were permitted for equity participation in the Joint Venture Company formed by M/s Torrent Export Limited and Gujarat Power Corporation Limited (GPCL) in the name of Gujarat Torrent Energy Corporation Limited (now renamed as Gujarat Powergen Energy Corporation Limited) to set up the 655 MW dual fuel power plant at Paguthan in Bharuch Distict. Apart from this, the following private sector power projects in the State accorded techno-economic clearance by the Central Electricity Authority (CEA) also envisage foreign equity

participation:—

i. Hazira CCGT (515 MW) of M/s Essar Power Limited.

ii. Jamnagar Project (500 MW) of M/s Reliance Power Limited.

(b) of the above, the Hazira and Paguthan projects (first phases) have already been commissioned.

(c) No, Sir, none of the projects in Gujarat having foreign equity participation are pending for techno-economic clearance by the CEA.

(d) Does not arise.

(e) As stated above, the Hazira (515 MW) and Paguthan (654.7 MW) projects have already been fully commissioned. The power shortage will be further reduced by around 500 MW once the Jamnagar project gets commissioned.

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Sir, as of today, what is the installed capacity of the Gujarat Electricity Board? Out of the installed capacity, how much is generated by the GEB and how much they are drawing from the Central sector like the NTPC and the Nuclear Power Corporation. Part (b) of my question is: What is the peak hour demand and what is the shortage of the Gujarat Electricity Board?

श्रीमती जयवंती मेहता: सभापति महोदय, अनेर में हमने बताया है और उसके अनुसार मैं यह बता सकती हूं कि गुजरात सरकार का सेंट्रल सेक्टर से जो शेयर है वह पूर्वा से 360, विंध्याचल से 469, कावा से 167, केकरापुर से 125, तारापुर से 160, कांधार से 237 मेगावाट है और निश्चित रूप से हम गुजरात के लिए सेंट्रल सेक्टर के माध्यम से विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं।

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Sir, my question has not been answered. What is the installed capacity of the GEB? What is the peak load shortage and what is the demand?

श्रीमती जयवंती मेहता: वैसे देखा जाए तो पहले जो कमी थी वह 4.3 प्रसेंट के बराबर थी लेकिन अब वह कमी धीरे-धीरे कम हो चुकी है और सिर्फ 2.3 परसेंट की कमी हो रही है।

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: How many megawatts? Sir, I would request the hon. Minister, Shri P. Kumaramangalam, either to reply to the question himself or allow the Minister of State to reply. I have not followed the answer. The reply is not clear.

श्रीमती जयवंती मेहता: अच्छा, एक सेकेंड में बता रही हूं। शॉर्टेज जो है वह 1999-2000 में 4208 मिलियन यूनिट्स है।

THE MINISTER OF POWER SHRI P. R. KUMARAMANGALAM: Mr. Chairman, Sir, with your permisison, I would like to intervene. Whenever we talk of power, we normally talk in terms of million units, in regard to shortage of power. Converting that into megawatts is normally difficult because megawatt is a section of current *vs.* capacity. When you look at power, when you assess the capacity, it is in megawatts, and when you talk of actual flow of power, you talk of million units. Conversion is usually done. When you talk of actual shortage, you talk of million units. He wanted to know the shortage of power, he got the figure in million units.

SHRI BRAHAMAKUMAR BHATT: May I know the status of the power projects supposed to be set up at Kandla based on imported coal? What is the present status and when is it likely to be given to the companies which are the bidders?

श्रीमती जयवंती मेहता: गुजरात में विदेशी कम्पनियों का जो निवेश है इसके लिए आपने कांडला के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं यह कहना चाहती हूं कि कांडला का इसमें कोई प्रादुर्भाव नहीं होता है। इसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर हम अलग से दे सकते हैं।

श्रीमती सविता शारदा: सभापति महोदय, गुजरात के सूरत शहर में दो अलग-अलग कम्पनियों द्वारा बिजली की सप्लाई होती है, एक जीईबी और दूसरी सूरत इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी। दोनों के भाव में बहुत फर्क है। वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत हैं। इसलिए दोनों कम्पनियों के भाव में असमानता होने के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री धीरे-धीरे मंदी की ओर जा रही है। दूसरे राज्यों और सूरत शहर के विद्युत भाव की दरों में बहुत ज्यादा फर्क है जिसके कारण वहां की इंडस्ट्री लगभग मृतप्राय: हो रही है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि इसके लिए सरकार की तरफ से कोई योजना है जिससे एक ही भाव पर पूरे शहर को विद्युत मिले ताकि वहां की इंडस्ट्री उन्नति की तरफ बढ़े?

श्रीमती जयवंती मेहता: आपका प्रश्न सूरत में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के संबंध में सवाल है इसलिए इस प्रश्न के साथ सम्बद्ध नहीं किया जा सकता है और सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके बारे में एक ही टैरिफ हो सके।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: सभापति महोदय, जो स्टेटेमेंट सभापटल पर रखा गया है इसमें गुजरात पावर कारपोरेशन लि. को री-नेम कर दिया गया है। ठीक, है, टोरेंट एक्सपोर्ट लि., गुजरता पावर कारपोरेशन को इस तरीके से री-नेम करके आगे चल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जामनगर और हजीरा दो जगह प आपने परमिशन दे दी और कमीशन भी हो गया। जामनगर में पावर प्लांट जो एक और कम्पनी है जिसकी एप्लीकेशन या परमिशन मांग की आपके डिपार्टमेंट

में पेंडिंग है। ऐसा अखबारों में निकला है कि वहां पर रिलाइंस के आने से और किसी दूसरी कम्पनी को वहां प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव आपकी मिनिस्ट्री में है? और कौन सी कम्पनी ने प्रमोशन मांगा है?

श्रीमती जयवंती मेहता: माननीय सदस्य ने जामगनर प्रोजेक्ट, हजीरा प्रोजेक्ट के बारे में जो सवाल पूछा है इसके लिए मैं यह कह सकती हूं कि सीमेंट पावर करेंट एक्सपोर्ट लि., गुजरात पावर कारपोरेशन इन कम्पनियों ने मिलकर मांग की थी और निश्चित रूप से इन कम्पनियों से बातचीत हुई है और उसके अनुसार यह कमीशंड हो चुका है। गैस और नाप्था दोनों से चलने वाला प्रोजेक्ट है। जामनगर प्रोजेक्ट के बोर में जहां तक संबंध है, रिलाइंस पावर प्रमोट कं है, इसके माध्यम से किया जाता है और ये ढ़ाई-ढ़ाई सौ मेगावाट के दो यूनिट हैं। विदेशी कंपनियो' की इक्विटी मिलियन डालर में ली जाती है और इसमें भारतीय इक्विटी भी है। इसमें टोटल 2,550.741 करोड़ का खर्च होने वाला है। इसके लिए मैं यह कह सकती हूं कि इसमें हस्ताक्षर हो चुके हैं और रिलाइंस कीजो पेटको कंपनी है, इसके माध्यम से इस योजना को चलाया जाएगा।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: मेरा सवाल यह नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जाम नगर में और भी कंपनियों ने अपने प्रस्ताव रखे हैं और रिलायंस की वजह से दूसरी कंपनियों को परमिशन नहीं दी जा रही है?

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: You put a straight question whether Essar is given permissionor not.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव आपके पास पेंडिंग हैं? यदि है तो आप परमिशन कब देंगे और यदि नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्रीमती जयवंती मेहता: आपने हजीरा के बारे में ...(व्यवधान)।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: हजीरा नहीं, मैं जाम नगर की बात कर रहा हूं मैडम। हजीरा के बारे में तो आपने बता दिया है।

श्रीमती जयवंती महेता: जाम नगर के लिए एस्सार या किसी और कंपनी की ओर से कोई प्रांग नहीं की गई है।

SHRI BACHANI LEKHRAJ: Sir, I want to know from the hon. Minister whether the Central Government has got any information regarding the proposal sent by Kaysurya Co. Ltd., London, to the Gujarat Government offering production of thermal energy using laser waste destruction system. If it is so,

what are the chances of that system? If not, will the Central Government call for the proposal to study the feasibility of that system?

श्रीमती जयवंती मेहता: मेरी जानकारी के मुताबिक गुजरात के लिए लंदन की किसी कंपनी से कोई मांग आई हो, ऐसी जानकारी भारत सरकार के पास नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Mr. Ramachandraiah. This is a question about Gujarat.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir my question is about foreign participation in power generation.

MR. CHAIRMAN : No. This is a specific question about Gujarat. Question No. 623.

सूखा-प्रवण क्षेत्रों को खेती-योग्य भूमि में बदलना

*623 **श्री रमा शंकर कौशिक†:**
प्रो. रामगोपाल यादव:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूखा-प्रभावित क्षेत्रों को खेती-योग्य भूमि में बदलने की सरकारी योजना कब से क्रियान्वित हुई है;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या सफलता मिली है तथा इस योजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या बंजर भूमि का विस्तार दिन-प्रतिदिन हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बंजर भूमि के विस्तार को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) को फसलों तथा पशुधन पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा इन क्षेत्रों को सूखे से मुख्त करने की दृष्टि से संबंधित क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार को पुन: स्थापित करने के मूल उद्देश्य के साथ वर्ष 1973-74 में शुरू

† सभा में यह प्रश्न श्री रमा शंकर कौशिक द्वारा पूछा गया।